RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 353
दि. 26.04.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मालखाने की लापरवाही या सिस्टम की विफलता? 'चूहों ने खा लिए सबूत' मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली से सामने आया एक मामला न केवल न्यायिक व्यवस्था, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आमतौर पर अदालतों में कई तरह की दलीलें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब साक्ष्य के रूप में पेश की जाने वाली रिश्वत की रकम के बारे में यह कहा जाए कि उसे चूहों ने कुतर डाला, तो यह केवल एक विचित्र तर्क नहीं रह जाता, बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर चोट करता है। इसी तरह के एक मामले में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराई गई महिला को जमानत देते हुए राज्य तंत्र की लापरवाही पर तीखी टिप्पणी की है।

यह मामला बिहार से जुड़ा है, जहां चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर के पद पर कार्यरत अरुणा कुमारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। आरोप था कि उन्होंने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में ट्रैप कार्रवाई के दौरान जो नकदी बरामद की गई, वही अदालत में मुख्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जानी थी। निचली अदालतों में सुनवाई के बाद पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

जब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो राज्य पुलिस की ओर से जो जानकारी सामने आई, उसने सबको चौंका दिया। अदालत को बताया गया कि रिश्वत के रूप में जब्त किए गए नोट पुलिस के मालखाने में रखे गए थे, लेकिन जब उन्हें पेश करने की बारी आई, तो वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। कारण बताया गया कि उन नोटों को चूहों ने कुतर दिया। यानी, जिस साक्ष्य के आधार पर अपराध साबित किया जाना था, वह अब अस्तित्व में ही नहीं था।

इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल थे, ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने स्पष्ट कहा कि साक्ष्यों का इस तरह गायब होना न केवल न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करता है,

बल्कि यह राज्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब चूहों के द्वारा साक्ष्य नष्ट होने का बहाना सामने आया हो। इससे पहले भी कई मामलों में इसी तरह के तर्क दिए गए हैं, जिनमें नशीले पदार्थों और नकदी के गायब होने की बात कही गई।

अदालत ने इस पूरे मामले को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक व्यापक समस्या का संकेत माना। न्यायमूर्तियों ने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस कस्टडी में रखे गए महत्वपूर्ण साक्ष्य सुरक्षित क्यों नहीं रखे जा सके। क्या मालखानों में साक्ष्य संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, या फिर यह लापरवाही का मामला है? अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं और आम जनता के भरोसे को भी चोट पहुंचाती हैं।

इस दौरान महिला के वकील ने अदालत में यह दलील दी कि जब मुख्य साक्ष्य ही नष्ट हो चुका है, तो सजा को बनाए रखना न्यायसंगत नहीं होगा, खासकर तब जब मामला अभी अपील के स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आरोपी को जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इस तर्क पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिला की सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया और उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला अंतिम नहीं है, बल्कि केवल तब तक के लिए है जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। यानी, दोषी ठहराई गई महिला को राहत जरूर मिली है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के मामलों में राज्य सरकारों और पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा और साक्ष्यों के संरक्षण के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

यह मामला कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। सबसे पहला सवाल यह है कि यदि साक्ष्य ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो न्याय प्रक्रिया कैसे निष्पक्ष और प्रभावी बनी रहेगी? दूसरा सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाएं केवल लापरवाही का परिणाम हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकते हैं? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हमारी जांच एजेंसियां और पुलिस तंत्र आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को अपडेट कर पा रही हैं या नहीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि साक्ष्यों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों को अपनाना समय की जरूरत है। डिजिटल रिकॉर्डिंग, सुरक्षित स्टोरेज सिस्टम और नियमित ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं लागू की जानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की लापरवाही करने से पहले सोचे।

यह मामला केवल एक महिला को मिली जमानत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे के लिए एक चेतावनी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने साक्ष्यों और न्याय प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त गंभीर हैं या नहीं। यदि इस घटना से सबक नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में इस तरह के और भी मामले सामने आ सकते हैं, जो न्याय व्यवस्था की नींव को कमजोर कर सकते हैं।

अंततः, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी और फैसला एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि न्याय केवल सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि साक्ष्य सुरक्षित रहें और न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। अब यह राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों पर निर्भर करता है कि वे इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं और अपने सिस्टम में सुधार के लिए क्या कदम उठाते हैं।

हुगली की धरती से राहुल का वार, भाजपा और टीएमसी दोनों पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में जैसे-जैसे मतदान के चरण आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाज़ी भी उतनी ही तीखी होती जा रही है। इसी क्रम में हुगली में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस दोनों पर एक साथ हमला बोलकर चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। उनके भाषण में केवल आरोप ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति और वैचारिक संघर्ष की झलक भी साफ दिखाई दी।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए यह मुद्दा उठाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज किए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने दावा किया कि इस अंतर के पीछे राजनीतिक कारण हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन पर 36 मामले दर्ज किए गए, उनकी लोकसभा सदस्यता छीनी गई और उन्हें लगातार कानूनी और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत, उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वे भाजपा के साथ सीधे

टकराव में नहीं हैं।

उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय का उल्लेख करते हुए कहा कि उनसे 55 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन ममता बनर्जी से किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं हुई। राहुल गांधी का यह बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार की एजेंसियों के उपयोग पर सवाल उठाने वाला था। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अपने भाषण में राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में उद्योगों का पतन हुआ है और बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि एक समय जो बंगाल औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी था, वह आज पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में निवेश का माहौल कमजोर हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई चर्चित घोटालों का भी जिक्र किया, जिनमें सारदा और रोज वैली जैसे बड़े वित्तीय घोटाले शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन घोटालों में हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई और आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने कोयला तस्करी, अवैध खनन और तथाकथित "गुंडा टैक्स" जैसे मुद्दों पर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार को घेरा। उनके अनुसार, इन सभी मामलों ने राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

राहुल गांधी ने केवल राज्य सरकार पर ही नहीं, बल्कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों पर भी वैचारिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के खिलाफ वैचारिक स्तर पर संघर्ष कर रही है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि देश के मूल्यों और संविधान की रक्षा की है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल चुनाव के समय ही ममता बनर्जी पर हमला करते हैं, जबकि बाकी समय दोनों के बीच कोई वास्तविक टकराव नहीं दिखता। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच एक प्रकार की "अप्रत्यक्ष समझ" है, जिससे कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

अपने भाषण में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे व्यवहार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है, जैसा देश के अन्य हिस्सों में भाजपा के शासन में होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के लोगों को डराया-धमकाया जाता है और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने की कोशिश की जाती है।

राहुल गांधी का यह बयान कि "ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा के लिए रास्ता खोल रही हैं" राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निर्वाचन का महासंग्राम: बंगाल में सुरक्षा के अभेद किले के बीच दूसरे चरण की तैयारी

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है और जैसे-जैसे मतदान के चरण आगे बढ़ रहे हैं, चुनावी रण और भी अधिक तीखा होता जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। 29 अप्रैल को होने वाले इस महत्वपूर्ण चरण में राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसे देखते हुए आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती का फैसला किया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि आयोग किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक के लिए तैयार नहीं है। कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, ये अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक अन्य राज्यों से बुलाए गए हैं ताकि स्थानीय प्रभाव से मुक्त रहकर वे निष्पक्ष तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। इनका मुख्य उद्देश्य मतदान प्रक्रिया की निगरानी करना, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और किसी भी संभावित हिंसा या अव्यवस्था को समय रहते नियंत्रित करना है। चुनाव आयोग का यह निर्णय राज्य में पहले चरण के दौरान सामने आई छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बाद लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को संपन्न हुआ था, जिसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, फिर भी कुछ स्थानों पर तनाव और झड़प की खबरें सामने आई थीं। इन घटनाओं ने आयोग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दूसरे चरण में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। यही कारण है कि आयोग ने पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या में वृद्धि करते हुए इसे 84 से बढ़ाकर 95 कर दिया है। यह बढ़ोतरी केवल संख्या का विस्तार नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम है, जिसके माध्यम से आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर संवेदनशील क्षेत्र पर कड़ी नजर रखी जा सके।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहले से ही संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और वहां निगरानी को और अधिक कड़ा किया गया है। पुलिस पर्यवेक्षकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे इन क्षेत्रों में जाकर स्थिति का आकलन करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को तुरंत रिपोर्ट करें। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों, वेबकास्टिंग और केंद्रीय बलों की मौजूदगी के जरिए भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

इन बाहरी राज्यों से आए अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस को सौंपी गई है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के दौरान कई बार स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दबाव या प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बाहरी अधिकारियों की तैनाती एक संतुलन बनाए रखने का काम करती है।

चुनाव आयोग का यह सख्त रुख इस बात को भी दर्शाता है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए न केवल सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बल्कि उन्हें स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में चुनाव हमेशा से ही राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील माने जाते रहे हैं, जहां विभिन्न दलों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखे। इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे इस दिशा में एक मजबूत प्रयास के रूप में देखे जा सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोग की यह सक्रियता मतदाताओं के विश्वास को मजबूत करेगी और मतदान प्रतिशत को भी प्रभावित कर सकती है। जब लोगों को यह भरोसा होता है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है, तो वे अधिक संख्या में मतदान के लिए बाहर निकलते हैं। यही लोकतंत्र की असली ताकत है, जिसे बनाए रखने के लिए आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आयोग की यह रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या दूसरे चरण का मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाता है। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है और वह हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बंगाल का यह सियासी रण अब केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि व्यवस्था और निष्पक्षता की कसौटी पर भी परखा जा रहा है, जहां हर कदम का महत्व है और हर निर्णय का प्रभाव दूरगामी हो सकता है।

इंफाल की सड़कों पर उफान, शांति की मांग ने लिया उग्र रूप

उत्तर-पूर्व के संवेदनशील राज्य मणिपुर में जारी जातीय तनाव और हिंसा के बीच शनिवार का दिन एक बार फिर उथल-पुथल भरा साबित हुआ। राजधानी इंफाल में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और स्थायी शांति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। यह प्रदर्शन धीरे-धीरे उग्र होता गया और सुरक्षा बलों के साथ आमना-सामना हो गया, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं और लोगों के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है।

यह विरोध प्रदर्शन मैतेई संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के आह्वान पर आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी अलग-अलग हिस्सों से चार रैलियों के रूप में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां, बैनर और नारे थे, जिनमें शांति बहाली, न्याय और पुनर्वास की मांग प्रमुख रूप से उठाई जा रही थी। प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करना था, जिनका समाधान लंबे समय से नहीं हो पाया है।

प्रशासन को पहले से इस प्रदर्शन की जानकारी थी, इसलिए मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बाबूपाड़ा क्षेत्र में स्थित मुख्यमंत्री आवास के चारों ओर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे। शहर के प्रमुख इलाकों—केसामपत जंक्शन, कांगला गेट, कोनुंग ममांग और मोइरांगखोंग—में बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके

बावजूद, भीड़ का उत्साह और आक्रोश इतना अधिक था कि उन्होंने कई जगहों पर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की।

स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब इंफाल पूर्वी जिले के खुरई लामलोंग इलाके में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। यह स्थान मुख्यमंत्री आवास से महज दो किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए प्रशासन के लिए यह एक संवेदनशील बिंदु बन गया। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी, तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर-उधर भागने लगे।

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो कारण हैं, वे केवल एक दिन या एक घटना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का परिणाम है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में हाल ही में बिष्णुपुर जिले में हुए बम विस्फोट में मारे गए दो मासूम बच्चों के लिए न्याय की मांग शामिल है। इस घटना ने लोगों के मन में गहरा आक्रोश पैदा किया है और वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं।

इसके अलावा, आंदोलनकारियों की एक बड़ी मांग उन हजारों लोगों के पुनर्वास से जुड़ी है, जो पिछले वर्ष 3 मई 2023 से शुरू हुए जातीय संघर्ष के कारण अपने घरों से विस्थापित हो गए थे। इन लोगों का जीवन आज भी राहत शिविरों में गुजर रहा है, जहां उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने अब तक उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे उनका धैर्य टूटता जा रहा है।

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि इतने लंबे समय से जारी हिंसा और तनाव के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। उनका कहना है कि बार-बार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे राज्य में सामान्य जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। व्यापार, शिक्षा और रोजमर्रा की गतिविधियां बाधित हो रही हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मणिपुर में स्थिति केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, जातीय और राजनीतिक जटिलताओं से जुड़ा हुआ है। जब तक इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर समाधान नहीं निकाला जाएगा, तब तक शांति बहाल करना कठिन होगा। इसके लिए सभी पक्षों के बीच संवाद, विश्वास बहाली और ठोस नीतिगत कदमों की आवश्यकता है।

इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि मणिपुर के लोग अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि राज्य में स्थायी शांति स्थापित हो, ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें। प्रदर्शनकारियों की आवाज में जो आक्रोश और पीड़ा झलक रही है, वह इस बात का संकेत है कि अब हालात को नजरअंदाज करना संभव नहीं है।

प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह एक ओर कानून-व्यवस्था बनाए रखे और दूसरी ओर लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करे। केवल बल प्रयोग से स्थिति को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि सरकार लोगों के साथ संवाद स्थापित करे, उनकी मांगों को गंभीरता से सुने और उन पर अमल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

इंफाल की सड़कों पर उमड़ी यह भीड़ केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संदेश है—एक ऐसा संदेश जो सरकार को यह याद दिलाता है कि शांति और स्थिरता केवल सुरक्षा बलों के सहारे नहीं, बल्कि न्याय, विश्वास और समानता के आधार पर ही स्थापित की जा सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस चुनौती का सामना किस तरह करती है और क्या वह मणिपुर को हिंसा के इस दौर से बाहर निकालने में सफल हो पाती है या नहीं।

संपादकीय

आप को बड़ा झटका

पंजाब में विधानसभा चुनाव से सिर्फ दस महीने पहले, राज्यसभा के सात सांसदों द्वारा आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने से पार्टी का संकट गहराता नजर आ रहा है। बगावती तेवरों वाले तीन राज्यसभा सदस्यों राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी में विभाजन की घोषणा करते हुए कहा है कि उच्च सदन में आप के दो-तिहाई सांसद यानी दस में सात सदस्यों ने एक गुट के रूप में भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का निर्णय कर लिया है। हाल के महीनों में खासे मुखर रहने वाले राघव चड्ढा को राज्यसभा में आप के उपनेता पद से हटाये जाने के बाद उनके द्वारा शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद तो विभाजन के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। विडंबना यह है कि राज्यसभा में राघव चड्ढा के स्थान पर आप के उप नेता की जगह लेने वाले अशोक मित्तल ने भी उनका ही साथ दिया है। इसमें दो राय नहीं कि बीते साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिये यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। एक समय था कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी में नई पीढ़ी का ऊर्जावान प्रतीक चेहरा माना जाता रहा है। अब वे ही आप नेतृत्व पर पार्टी के मूलभूत आदर्शों से पीछे हटने का आरोप लगा रहे हैं। राघव व पार्टी के अन्य बागी सांसदों ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी जनसरोकारों को प्राथमिकता देने के बजाय निजी लाभ को तरजीह दे रही है। उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ही हैं। जिन्हें पंजाब में मान सरकार की बागडोर दिल्ली से संचालित करने वाला माना जाता रहा है। जैसा कि आपेक्षित था, आबकारी नीति मामले में मुश्किल में फंसे और अदालती लड़ाई लड़ रहे केजरीवाल ने इन सांसदों पर विश्वास तोड़ने और पंजाब की जनता से छल करने का आरोप लगाया है।

केजरीवाल ने आप से अलग होने वाले सांसदों पर पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात करने वाला बताया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी केजरीवाल के निशाने पर है, जिस पर उन्होंने सुनियोजित साजिश करके आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वास्तव में भाजपा सीमावर्ती राज्य पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में भगवा पार्टी ने हाल के वर्षों में पंजाब के कई कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में करने में कामयाबी पायी है। निश्चित रूप से राज्य सभा में आप के दो तिहाई सांसदों का टूटकर भाजपा में मिलना आम आदमी पार्टी के लिये बड़ी चुनौती है। जिसके चलते पंजाब में अपनी खोई जमीन पाने के लिये पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आप के कुछ और नेता आगामी दिनों में भाजपा का दामन थाम लें। लेकिन यहां सवाल आप सुप्रीमो पर उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने इन नेताओं को राज्यसभा का टिकट देते वक्त पार्टी की रीति-नीतियों की कसौटी पर परखा था या फिर पार्टी की आर्थिक प्राथमिकताओं को ही उनकी योग्यता मान लिया गया था। जाहिर है ये लोग सार्वजनिक जीवन में बहुत चर्चित चेहरे होने के बजाय आर्थिक रूप से समृद्ध लोग रहे हैं। जब चयन में आर्थिक प्राथमिकताएं होती हैं तो चयनित सदस्यों के निर्णय में भी लाभ-हानि का गणित ही प्रभावी रहता है। यहां सवाल कुछ सासंदों के कारोबारी छिद्रों पर सरकारी एजेंसियों का दबाव का भी है, जिन पर पिछले दिनों कार्रवाई भी हुई थी। अनुमान लगाये जा रहे हैं कि शायद इस कार्रवाई के बाद विभिन्न कारोबार से जुड़े अन्य सांसद भी दबाव में आ गए। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ राजग की धुलाई मशीन से गुजरना ज्यादा सुरक्षित महसूस किया। बहरहाल, इस घटनाक्रम ने अन्य राज्यों में विपक्षी दलों के लिये भी खतरे की घंटी बजा दी है। निश्चय ही इंडी गठबंधन के लिये अपने दलों को एकजुट रखना आने वाले दिनों चुनौती साबित हो सकता है।

आम आदमी पार्टी पर बड़ा संकट-केजरीवाल कब छोड़ेंगे पार्टी सुप्रीमो की कुर्सी?

> “ आंदोलन के समय के दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर केजरीवाल ने जिस राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे नेताओं को पार्टी का बड़ा चेहरा बनाया, उन्होंने ही एक झटके में केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। इन नेताओं ने सिर्फ केजरीवाल को झटका ही नहीं दिया, बल्कि राज्यसभा में एक तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म ही कर दिया।

आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल अपने सांसदों द्वारा 24 अप्रैल को उन्हें दिए गए गिफ्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे। सरकार से लड़-भिड़कर केजरीवाल ने अदालत के जरिए जो सरकारी बंगला लिया था, उस बंगले में परिवार सहित शिफ्ट होने की जानकारी केजरीवाल ने जिस दिन सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसी दिन उनके भरोसेमंद सांसदों ने उनकी पार्टी ही तोड़ दी। आंदोलन के समय के दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर केजरीवाल ने जिस राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे नेताओं को पार्टी का बड़ा चेहरा बनाया, उन्होंने ही एक झटके में केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। इन नेताओं ने सिर्फ केजरीवाल को झटका ही नहीं दिया, बल्कि राज्यसभा में एक तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म ही कर दिया।

राघव चड्ढा की जिस काबलियत को देखकर एक जमाने में कुमार विश्वास, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इंटर्न के तौर पर पार्टी के साथ जोड़ा था। उसी काबलियत का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही चालाकी से राघव चड्ढा ने आप के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 का जुगाड़ (खुद को मिलाकर) करते ही बीजेपी का दामन थाम लिया।टूट के लिए कानूनी रूप से जरूरी दो-तिहाई सांसदों का जुगाड़ कर एक बार फिर से राघव चड्ढा ने अपनी काबलियत तो साबित कर दी लेकिन इस बार वे अपने ही राजनीतिक गुरु केजरीवाल पर भारी पड़ गए।

पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, जिस पार्टी को खून-पसीने से सींचा वह अपने सिद्धांतों से भटक गई है। वहीं केजरीवाल ने अपने राजनीतिक स्टाइल के मुताबिक, बीजेपी पर पंजाबियों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी और उनके पूरे सिस्टम ने इन्हें गद्दार, यहां तक कि देशद्रोही तक साबित करने का अभियान छेड़ दिया है।

जबकि होना तो यह चाहिए था कि इतनी बड़ी टूट के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं, खासकर आंदोलन के समय के नेताओं को बैठकर आत्ममंथन करना चाहिए। वर्ष 2013 से पहले और उसके बाद आए तमाम नेताओं पर नजर डालते हुए, यह सोचना चाहिए कि अब तक कितने गए, कब गए, क्यों गए और किसकी वजह से गए? लेकिन इसकी बजाय केजरीवाल पार्टी छोड़कर जाने वाले हर नेता को गद्दार साबित करने में जुट जाते हैं ताकि पार्टी के अंदर कोई भी उनके रवैए पर सवाल न उठा पाए।

आप का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए देशव्यापी आंदोलन से हुआ था इसलिए इस पार्टी का खत्म होना दशकों तक इस देश को आंदोलन के नाम से डराता रहेगा। इसके लिए सिर्फ ऑपरेशन लोटस और बीजेपी को जिम्मेदार बता देने से काम नहीं चलेगा। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को तुरंत पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाकर कुछ कड़े फैसले लेने की पहल करनी चाहिए। दिल्ली में मिली हार के बाद अब यह सवाल तो बेमानी हो गया है कि ‘एक व्यक्ति, एक पद’ के नियम के बावजूद अरविंद केजरीवाल वर्षों तक दो-दो पदों पर कैसे बने रहे? लेकिन अब यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि आखिर पिछले साढ़े 13 वर्षों से एक ही व्यक्ति (अरविंद केजरीवाल) पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक क्यों बने हुए हैं? क्या संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या पार्टी के किसी भी अन्य नेता में पार्टी की कमान संभालने की क्षमता नहीं है ? नेताओं को पार्टी से निकालने का मामला हो या राज्यसभा उम्मीदवार तय करने का मामला हो, यह सब कुछ एक ही व्यक्ति की इच्छा पर कब तक छोड़ा जाएगा? आखिर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी क्यों बनाई गई है और इसका काम क्या है? पहले दिल्ली में सत्ता सुख भोगों और जब यहां पर जनता सत्ता से बाहर कर दें तो पंजाब जाकर जम जाओ, ये किस तरह का रवैया है? चाहे वो केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया या फिर बिभव कुमार या फिर कोई अन्य नेता या कर्मचारी, दिल्ली की हार के बाद क्या ये लोग 3-4 साल भी दिल्ली में या देश के अन्य राज्यों में संघर्ष नहीं कर सकते जो ये लोग सत्ता वाले राज्य पंजाब को घर बनाने निकल पड़ते है? अगर इन सवालों के जवाब नहीं तलाशे गए तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में आप का पूरा संगठन भी बीजेपी में विलय होता हुआ नज़र आएगा।

अगर यह सब सिर्फ एक या दो व्यक्ति की जिद के कारण हो रहा है तो पार्टी के सभी नेताओं को मिलकर उन्हें किनारे लगाकर किसी और सक्षम नेता को जिम्मेदारी देनी चाहिए। पार्टी को अपने पुराने नेताओं की भी घर वापसी का अभियान बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए और सबसे बड़ी बात आप के नेताओं को यह समझना चाहिए कि राज्यसभा की सांसदी का टिकट धन्नासेठों के लिए नहीं पार्टी के समर्पित कार्यकताओं के लिए होता है।

राजनीतिक हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, अगर उससे भी ज्यादा तेजी से आप ने बदलाव नहीं किए तो आने वाले दिनों में पार्टी के नाम और निशान दोनों पर ही बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बिभव कुमार, भगवंत मान और आतिशी इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं?

प्रेरणा

आकर्षण से परे धर्म की ज्योति

श्रावस्ती की शांत भूमि पर एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ, जो मानव मन की गहराइयों और उसकी प्रवृत्तियों को समझने का अद्भुत अवसर देता है। यह कथा है ब्राह्मण वक्कलि की, जो बाहरी सौंदर्य के आकर्षण में उलझकर अपने वास्तविक आध्यात्मिक कर्तव्य से भटक गया था। जब उसने गौतम बुद्ध की दिव्य छवि को देखा, तो वह इतना अभिभूत हो गया कि उसने तुरंत उनके शिष्य बनने का निर्णय कर लिया। उसके भीतर श्रद्धा तो जागी, लेकिन वह श्रद्धा धीरे-धीरे आसक्ति में बदल गई।

वक्कलि का मन बुद्ध के व्यक्तित्व के तेज और उनके सौम्य रूप में इस तरह डूब गया कि वह अपने भिक्षु धर्म के मूल उद्देश्य को ही भूल बैठा। वह दिन-रात केवल बुद्ध के मुखमंडल की आभा को निहारता रहता, मानो वही उसके लिए अंतिम सत्य हो। उसके लिए ध्यान, साधना और आत्मानुशासन गौण हो गए। वह यह समझ ही नहीं पाया कि जिस प्रकाश को वह बाहरी रूप में देख रहा है, उसका वास्तविक स्रोत भीतर की साधना और आत्मबोध में है।

जब बुद्ध ने यह देखा कि वक्कलि अपने मार्ग से विचलित हो रहा है, तो उन्होंने उसे प्रेमपूर्वक समझाया। उन्होंने कहा कि बाहरी सौंदर्य नश्वर है, वह समय के साथ नष्ट हो जाता है। शरीर की सुंदरता, चेहरे की आभा, यह सब परिवर्तनशील है। लेकिन धर्म की जो आभा होती है, वह शाश्वत होती है, वह आत्मा को प्रकाशित करती है और जीवन को सही दिशा देती है। बुद्ध का यह संदेश केवल वक्कलि के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक चेतावनी थी कि हमें बाहरी आकर्षण के मोह में फंसकर अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए।

यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आधुनिक युग में बाहरी सौंदर्य का आकर्षण पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और भौतिकवाद ने हमें इस हद तक प्रभावित कर दिया है कि हम अक्सर बाहरी रूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। लोग अपने शरीर को सजाने-संवारने में इतना समय और ऊर्जा लगाते हैं कि आत्मिक विकास की ओर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि बाहरी सौंदर्य केवल एक क्षणिक छवि है, जो समय के साथ मुरझा जाती है।

धर्म का वास्तविक सौंदर्य उसके सिद्धांतों में, उसके आचरण में और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली आंतरिक शांति में निहित होता है। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसके भीतर एक अलग ही प्रकार का तेज उत्पन्न होता है। यह तेज किसी बाहरी श्रृंगार का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह उसके विचारों की शुद्धता, उसके कर्मों की पवित्रता और उसकी आत्मा की निर्मलता से उत्पन्न होता है। यही वह सौंदर्य है जो कभी नष्ट नहीं होता।

वक्कलि की भूल यही थी कि उसने बाहरी रूप को ही अंतिम सत्य मान लिया। उसने यह नहीं समझा कि बुद्ध का आकर्षण उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और उनके आत्मबोध में है। यदि वह उस ज्ञान को आत्मसात करता, तो वह स्वयं भी उसी दिव्यता को प्राप्त कर सकता था। लेकिन बाहरी रूप के मोह में पड़कर उसने अपने भीतर की यात्रा को रोक दिया।

यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि श्रद्धा और आसक्ति में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। श्रद्धा हमें ऊपर उठाती है, हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। लेकिन आसक्ति हमें बांध लेती है, हमें एक ही स्थान पर रोक देती है। वक्कलि की श्रद्धा आसक्ति में बदल गई, और यही उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन गई।

धर्म का सौंदर्य किसी मूर्ति, किसी व्यक्ति या किसी बाहरी वस्तु में सीमित नहीं होता। वह तो एक अनुभूति है, एक चेतना है, जो भीतर से प्रकट होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने दोषों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तभी हम उस वास्तविक सौंदर्य को अनुभव कर पाते हैं। यह सौंदर्य हमें स्थायी सुख और शांति प्रदान करता है।

बुद्ध का यह संदेश कि “शारीरिक सौंदर्य के प्रति आसक्ति पतन का कारण बनती है” आज के संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आज का समाज बाहरी दिखावे पर आधारित होता जा रहा है। लोग अपनी पहचान अपने रूप, अपने वस्त्र और अपनी भौतिक उपलब्धियों से जोड़ने लगे हैं। लेकिन यह सब क्षणभंगुर है। वास्तविक पहचान हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे चरित्र से बनती है।

यदि हम वक्कलि की कथा से सीख लें और अपने जीवन में धर्म के वास्तविक सौंदर्य को अपनाने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और संतुलित हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि बाहरी आकर्षण केवल एक भ्रम है, जबकि आंतरिक शांति ही सच्चा आनंद है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी सौंदर्य की आवश्यकता नहीं रह जाती।

अंततः, यह कथा हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी कहीं वक्कलि की तरह बाहरी आकर्षण में उलझकर अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल तो नहीं रहे हैं? यदि हां, तो हमें समय रहते संभल जाना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। क्योंकि धर्म का सौंदर्य ही वह प्रकाश है, जो हमें अंधकार से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है, और यही वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं।

भारत नरक नहीं, स्वर्ग का अहसास है, मानवता का वैभव, सभ्यता का प्रकाश है!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अब तक कई बार ऐसे तीखे या अपमानजनक बयान दिए हैं जिनके पश्चात उन्होंने या तो रुख बदल दिया या सॉफ्ट स्टेटमेंट जारी करके अपनी बात पर “यू टर्न” लेकर साफ साफ मुकर जैसा अंदाज़ दिखाया है। हाल ही में फिर उन्होंने “नरक जैसा देश” वाला बयान दिया और फिर यू टर्न ले लिया। उनका रवैया दुनिया का थानेदार समझे जाने वाले सर्वाधिक विकसित और धनी देश अमेरिका के शालीन, सभ्य और सुसंस्कृत होने पर सवालिया निशान लगाने को काफी है। खासकर भारत के खिलाफ जिसका अंतर्राष्ट्रीय आचरण सदैव मर्यादित रहता आया है। भारत पैसे वालों की कद्र नहीं करता, क्योंकि यह तो देशी-विदेशी अपराधियों और वेश्याओं के पास भी खूब होता है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं होती। ट्रंफ के नेतृत्व में अमेरिका इसी फूहड़ता से ग्रसित है, अभिशप्त है और अंतर्राष्ट्रीय गुंडई में इतना आगे निकल चुका है कि उसके मित्र देश भी उसके साथ खड़े होने में परहेज कर रहे हैं और उसे यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। ईरान-अमेरिका युद्ध ने अमेरिका की पूरी मिट्टी पलीद कर दी है और उसके डीप स्टेट की जो भद्द पिटी है, वैसा कोई उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। शायद इसी खीझ का नाता ट्रंफ के नारकीय विवाद से है।

आइए, जानते हैं कि सबसे हाल का विवाद 24 घंटे में ही कैसे दोनों ध्रुवों पर घूम गया, जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “ट्रुथ सोशल” पर एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट का हिस्सा शेयर किया, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को “नरक” (hell-holes / hell on earth) जैसी जगह बताया गया। इस पोस्ट में भारतीयों के बारे में नस्लवादी टिप्पणी भी थी कि भारत–चीन से लोग अमेरिका आते हैं बस यहीं बच्चे पैदा करने के लिए ताकि उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिकता मिल जाए, जो भारतीय डिप्लोमैसी और जनता के लिए बेहद अपमानजनक माना गया।

फिर अगले ही नए बयान में ट्रंप ने रुख पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि समझ में आ गया कि ये मोदी का भारत है, चुपचाप उल्टा लटका देगा। कोई काम नहीं आएगा, जब कूटनीतिक शतरंज की एक चाल चल देगा तो। लिहाजा, उन्होंने जनता के बीच और अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता के ज़रिए कहा कि भारत “एक महान देश” (a great country) है, “मजबूत और महान राष्ट्र” है और भारत के शीर्ष नेता (प्रधानमंत्री मोदी) के साथ उनकी “निजी दोस्ती” है। काबिलेगौर है कि इस तरह 24 घंटे के अंदर वही शख्स जो भारत को “hard to deal with” या नरक जैसी जगह कह चुके थे, उसी देश की तारीफ़ में बोलने लगे, जिसे राजनीतिक यू टर्न और दबाव में बदला गया माना जा रहा है।

अब इनकी टैरिफ और “टैरिफ किंग” वाली पुरानी टिप्पणी को स्मरण करा देते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने व्यापार के मसले पर भी दोहरा अपना बयान दिया है। अपने कई इंटरव्यू और भाषणों में उन्होंने भारत को “टैरिफ किंग” (tariff king) कहा है, और यह कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाने वाले देशों में से एक है, जिससे अमेरिकी उत्पादों को नुकसान होता है। इसी क्रम में उन्होंने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी, लेकिन एक ही हवन में ही यह भी कहा कि भारत के साथ “बहुत अच्छे संबंध” हैं, यानी एक ही बयान में औपचारिक तारीफ़ और व्यावहारिक धमकी दोनों। निष्कर्षन के तौर पर पैटर्न यह दिखता है कि ट्रंप ने भारत के लिए एक बार नफरत भरी, नस्लवादी, “नरक जैसा देश” वाली भाषा इस्तेमाल की, और फिर तुरंत मिटाने के लिए भारत को “महान देश” और प्रधानमंत्री मोदी को “अपना दोस्त” कहकर मुकर जैसा कर दिया।

वहीं, व्यापार के मोर्चे पर भारत को “टैरिफ किंग” और हानिकारक बताने के साथ साथ राजनयिक रूप से “अच्छे रिश्ते” बताकर दोहरा रुख अपनाया है। इसी प्रकार ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी भी करार दे चुके हैं टैरिफ वार की खींझ में। उनके इस रवैये से भारत का अविश्वास अमेरिका और उनके प्रति बढ़ा है।

स्पष्ट है कि अमेरिका के सफल बिजनेसमैन और शातिर राजनेता से राष्ट्रपति बने डॉनल्ड ट्रंफ अपने सिरफिरे विचारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब से वो डीप स्टेट के हाथों का खिलौना बने, अपने अनाप-शनाप और अदूरदर्शिता भरे फैसलों से अंतरराष्ट्रीय जगत में अमेरिका की थू-थू करवा रखी है। पहले ट्रेड वार और अब सैन्य वार के बाद उसकी जो अंतरराष्ट्रीय फजीहत हुई है, उसके जैसे सो कॉल्ड देश ताकतवर की कलई खुल गई। यूक्रेन से शुरू हुई कूटनीतिक दोगलागिरी ईरान पहुंचते-पहुंचते न केवल चारो खाने चित्त हो गई, बल्कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंफ की बयानबाजी अब समझदार लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखी। कभी वह भारत को “डेड इकोनॉमी” बताते हैं, तो कभी नरक जैसा देश! शायद इसलिए कि भारतीय नेतृत्व उनके इशारों पर नहीं थिरक रहा है, जिससे रूस-चीन भी उसे भाव देना बंद कर चुके हैं।

दुनिया का थानेदार अमेरिका को बेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद जब कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने यह समझ लिया कि रूस-चीन भी उससे डरे हुए हैं। इसी उत्साह में अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर धावा बोल दिया और महज दो माह के भीतर ही परेशान हो उठा। इससे ईरान-रूस-चीन की संयुक्त ताकत का उसको एहसास हुआ। वहीं इसी मुद्दे पर नाटो में फूट भी पड़ गई और यूरोप तटस्थ बन गया। इसी बौखलाहट में ट्रंफ भारत और चीन को नरक जैसा बताने लगे।

बताते चलें कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं को “नरक” बताने का संदर्भ हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता (birth-right citizenship) के मुद्दे पर भारत-चीन को “hellhole” कहा। यह बयान ट्रंप की इमीग्रेशन पॉलिसी से प्रेरित है, जहां वे आरोप लगाते हैं कि इन देशों से प्रवासी अमेरिका की सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं। जबकि ऐतिहासिक वास्तविकता कुछ और है, जो कई मायने में गौरवशाली भी है।

अभियान

हिमालय की गोद में छिपे बद्रीनाथ के दिव्य स्थलों की अद्भुत यात्रा

उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी पर्वतों के बीच बसा बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि आस्था, आध्यात्मिकता और प्रकृति की दिव्यता का ऐसा संगम है, जहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं को एक अलग ही लोक में अनुभव करता है। वर्ष 2026 में 23 अप्रैल को जैसे ही इस पवित्र धाम के कपाट खुले, लाखों श्रद्धालुओं के मन में भक्ति की एक नई लहर दौड़ पड़ी। चारधाम यात्रा का यह महत्वपूर्ण पड़ाव सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। धार्मिक मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के इस पवित्र धाम के दर्शन करने से व्यक्ति जन्म और मरण के अनंत चक्र से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्गों को पार करके यहां पहुंचते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं।

लेकिन बद्रीनाथ की यात्रा का अनुभव केवल मंदिर के दर्शन तक सीमित नहीं है। इसके आसपास कई ऐसे दिव्य और रहस्यमयी स्थल स्थित हैं, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनके साथ जुड़ी कहानियां और वहां का वातावरण मन को गहराई तक स्पर्श करता है। जब कोई यात्री इन स्थलों की ओर कदम बढ़ाता है, तो वह केवल एक दर्शक नहीं रहता, बल्कि एक साधक बन जाता है, जो अपने भीतर छिपे सत्य को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ता है।

बद्रीनाथ के पास स्थित भविष्य बद्री एक ऐसा स्थल है, जो भविष्य की आस्था और रहस्य से जुड़ा हुआ है। यह स्थान जोशीमठ के समीप स्थित है और अत्यंत शांत वातावरण में बसा हुआ है। मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और नर-नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब वर्तमान बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। उस समय भगवान विष्णु का वास भविष्य बद्री में होगा। इस विश्वास के कारण यह स्थान विशेष महत्व रखता है। यहां की निस्तब्धता और प्राकृतिक सुंदरता व्यक्ति को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। ऐसा लगता है जैसे यह स्थान हमें यह संदेश दे रहा हो कि समय बदलता रहता है, लेकिन आस्था का स्वरूप हमेशा स्थिर रहता है।

इसी क्षेत्र में स्थित व्यास गुफा भारतीय ज्ञान परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है। यह गुफा माना गांव के पास स्थित है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में बैठकर चारों वेदों और महाभारत का संकलन किया था। इस गुफा की बनावट अत्यंत अद्भुत है। इसकी छत ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी विशाल पुस्तक के पन्ने एक के ऊपर एक रखे गए हों। इसलिए इसे “व्यास पुस्तक” भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति इस गुफा के भीतर प्रवेश करता है, तो उसे एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे ज्ञान की वह धारा, जो हजारों वर्षों पहले यहां प्रवाहित हुई थी, आज भी वहां विद्यमान है और हर आने वाले को प्रेरित कर रही है।

बद्रीनाथ के निकट स्थित भीम पुल एक ऐसा स्थान है, जहां पौराणिक कथा और प्राकृतिक चमत्कार एक साथ दिखाई देते हैं। यह पुल सरस्वती नदी के उफनते प्रवाह के ऊपर बना हुआ है और इसकी संरचना देखकर आश्चर्य होता है कि यह कैसे संभव हुआ होगा। मान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके मार्ग में यह प्रचंड नदी आई। उस समय भीम ने एक विशाल पत्थर उठाकर नदी पर रख दिया, जिससे सभी लोग सुरक्षित रूप से पार कर सके। आज भी यह पत्थर उसी रूप में मौजूद है और इसे देखकर श्रद्धालुओं के मन में आस्था और आश्चर्य का मिश्रण उत्पन्न होता है। यहां बहती सरस्वती नदी की गर्जना और चारों ओर फैली पर्वतों की भव्यता इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती है।

इसके बाद आता है वसुधारा झरना, जो प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण है। यह झरना बद्रीनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसकी जलधारा सूर्य की किरणों में मोतियों की तरह चमकती है और देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहां तक पहुंचने के लिए एक सुंदर ट्रेक करना पड़ता है, जो अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। मान्यता है कि इस झरने की बूंदें केवल उसी व्यक्ति को स्पर्श करती हैं, जिसका मन और कर्म शुद्ध होता है। यदि किसी के ऊपर पाप का बोझ होता है, तो यह जल उसे स्पर्श नहीं करता। यह विश्वास इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देता है और यहां आने वाले हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है।

बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहां स्नान करते हैं, क्योंकि इसे शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी कम क्यों न हो। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं और माना जाता है कि इसमें स्नान करने से शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति के अद्भुत रहस्यों में से एक भी है, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का विषय बना हुआ है।

इन सभी स्थलों की यात्रा करने पर यह अनुभव होता है कि बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक संसार है। यहां हर पत्थर, हर नदी और हर पर्वत अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष भी है, जिसे समझना और अनुभव करना आवश्यक है।

जब कोई व्यक्ति इन दिव्य स्थलों की यात्रा करता है, तो वह केवल अपने पापों से मुक्ति की कामना नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर की अशांति और भ्रम से भी मुक्त होने का प्रयास करता है। हिमालय की शांति, नदियों की मधुर ध्वनि और मंदिरों की घंटियों की गूंज मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो मनुष्य के मन को शुद्ध करता है और उसे एक नई दिशा प्रदान करता है। आज के आधुनिक जीवन में, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव और चिंता से घिरा हुआ है, ऐसे स्थान हमें एक नई ऊर्जा और संतुलन प्रदान करते हैं। यह हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद बाहरी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। बद्रीनाथ और उसके आसपास के ये दिव्य स्थल हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। इसलिए यदि आप बद्रीनाथ की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो केवल मंदिर के दर्शन तक ही सीमित न रहें। इन अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों की यात्रा भी अवश्य करें। यह यात्रा आपके जीवन को न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेगी, बल्कि आपको अपने भीतर झांकने और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का अवसर भी प्रदान करेगी। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहन और दिव्य यात्रा बना देती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

डी-कंपनी को बड़ा झटका: इस्तांबुल में दबोचा गया सलीम डोला, अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क पर शिकंजा

वैश्विक अपराध जगत में सक्रिय भारतीय अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को उस समय बड़ा झटका लगा, जब तुर्की के इस्तांबुल में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला को गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम डोला को अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी और उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का अहम स्तंभ माना जाता है। इस गिरफ्तारी को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी सफलता बताया है, क्योंकि इससे न केवल डी-कंपनी के नेटवर्क को झटका लगा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के कई छिपे पहलुओं के उजागर होने की संभावना भी बढ़ गई है।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई भारतीय एजेंसियों और तुर्की की खुफिया एजेंसी के बीच साझा खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। सलीम डोला लंबे समय से फर्जी पहचान के साथ तुर्की में रह रहा था और अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था, ताकि किसी भी तरह की निगरानी से बच सके। बताया जा रहा है कि वह एक फर्जी यूएई पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसकी असली पहचान छिपी रही। लेकिन तकनीकी निगरानी और खुफिया समन्वय के चलते अंततः उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई और एक संयुक्त अभियान में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के समय उसके पास से कई डिजिटल डिवाइस, संदिग्ध दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड मिलने की बात सामने आई है। हालांकि इन बरामदगियों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती संकेत यही बताते हैं कि ये दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क के संचालन से जुड़े हो सकते हैं। यदि इनकी पुष्टि होती है, तो इससे पूरे नेटवर्क की संरचना, उसके फंडिंग चैनल और वैश्विक संपर्कों का खुलासा हो सकता है।
जांच एजेंसियों का मानना है कि सलीम डोला दुबई में बैठकर अपने नेटवर्क को संचालित करता था। दुबई उसके लिए एक प्रमुख संचालन केंद्र था, जहां से वह सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई और वित्तीय लेनदेन को नियंत्रित करता था। यह नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि खाड़ी देशों, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। हर साल इस नेटवर्क के जरिए हजारों करोड़ रुपये का अवैध कारोबार होता था, जिसे हवाला और फर्जी कंपनियों के माध्यम से विभिन्न देशों में ट्रांसफर किया जाता था।
सलीम डोला लंबे समय से भारतीय एजेंसियों की वांटेड सूची में शामिल था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मुंबई पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज किए थे। इसके अलावा इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जो यह दर्शाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी था। इसके बावजूद वह वर्षों तक कानून की पकड़ से बाहर रहा, जो उसके नेटवर्क और संसाधनों की ताकत को दिखाता है।
अब जब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो सबसे बड़ी चुनौती उसे भारत लाने की है। भारत और तुर्की के बीच औपचारिक प्रत्यर्पण संधि का अभाव इस प्रक्रिया को जटिल बनाता है। ऐसे में भारतीय एजेंसियां इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय कानूनी तंत्रों के माध्यम से उसे भारत लाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। इसके लिए कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास किए जा सकते हैं, ताकि कानूनी बाधाओं को दूर किया जा सके।
सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह गिरफ्तारी केवल एक आरोपी को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सलीम डोला से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, जिनमें ड्रग्स सप्लाई चेन, हवाला नेटवर्क, फंडिंग के स्रोत और विदेशी ठिकानों की जानकारी शामिल हो सकती है। इससे न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को गति मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के नेटवर्क केवल अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होते हैं, क्योंकि इनके जरिए आतंकवादी गतिविधियों को भी वित्तीय सहायता मिल सकती है। ऐसे में सलीम डोला की गिरफ्तारी को केवल ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।
यह घटना यह भी दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और खुफिया साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। जब विभिन्न देशों की एजेंसियां मिलकर काम करती हैं, तो बड़े से बड़े अपराधियों को भी पकड़ा जा सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस गिरफ्तारी से कितने बड़े खुलासे होते हैं और क्या वास्तव में डी-कंपनी के नेटवर्क को कमजोर किया जा सकता है।
फिलहाल, इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून के लंबे हाथ से बचना आसान नहीं है। चाहे अपराधी कितनी भी दूर क्यों न छिपा हो, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए उसे पकड़ना संभव है। सलीम डोला की गिरफ्तारी इसी का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है, जिसने वैश्विक अपराध जगत में हलचल मचा दी है।

भावनगर मंडल अस्पताल द्वारा विश्व मलेरिया दिवस पर व्यापक जन-जागरूकता अभियान आयोजित

विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा मंडल के विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों एवं मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य रेलवे कॉलोनियों, स्टेशन परिसरों तथा आम जनता को मलेरिया रोग, उसके कारण, लक्षण, रोकथाम एवं उपचार के प्रति जागरूक करना था।

अभियान के अंतर्गत मंडल के प्रमुख स्टेशनों—भावनगर परा, धोलका, बोटाद, वेरावल, जूनागढ़ एवं जेतलसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विविध गतिविधियाँ संचालित की गईं। इन गतिविधियों में डोर-टू-डोर जागरूकता, पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शन, पंपलेट वितरण तथा व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से लोगों को मलेरिया से बचाव की जानकारी दी गई।

स्वास्थ्य कर्मियों ने रेलवे कॉलोनियों में घर-घर जाकर बताया कि मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। साथ ही बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, उल्टी, कमजोरी एवं शरीर दर्द जैसे प्रमुख लक्षणों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया।

जागरूकता अभियान के दौरान नागरिकों को निम्नलिखित सावधानियां अपनाने की सलाह दी गईः घरों एवं आसपास पानी जमा न होने देना, कूलर एवं पानी की टंकियों की नियमित सफाई करना, मच्छरदानी का उपयोग करना, पूर्ण बाजू के कपड़े पहनना, लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय जांच कराना, साथ ही मच्छरों की उत्पत्ति रोकने हेतु स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया।

मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर में भी मरीजों एवं कर्मचारियों को मलेरिया की रोकथाम, समय पर जांच एवं उपचार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अस्पताल परिसर में पोस्टर एवं सूचना सामग्री प्रदर्शित कर जागरूकता बढ़ाई गई।

भावनगर मंडल में आयोजित यह जागरूकता अभियान अत्यंत सफल एवं प्रभावी रहा। इसके माध्यम से रेलवे कर्मचारियों, कॉलोनी निवासियों एवं आम जनता में मलेरिया के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई तथा स्वच्छता एवं बचाव उपायों को अपनाने का महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित हुआ।

नए वैश्विक समीकरणों में उभरती धुरी: भारत-ताइवान साझेदारी से बदल सकता है एशिया का आर्थिक नक्शा

नई दिल्ली। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्संतुलन के दौर में भारत और ताइवान के बीच सहयोग तेजी से एक नई ऊंचाई पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ताइवानी मीडिया और विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों की आर्थिक संरचनाएं और क्षमताएं इस तरह एक-दूसरे के पूरक हैं कि उनका तालमेल आने वाले वर्षों में एशिया ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को भी प्रभावित कर सकता है। यह साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, विनिर्माण, कृषि और कौशल विकास जैसे व्यापक क्षेत्रों में फैली हुई है।
ताइवान की प्रमुख ताकत उच्च तकनीकी विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी अग्रणी भूमिका है। दूसरी ओर, भारत आईटी सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास और विशाल कुशल कार्यबल के लिए जाना जाता है। जब ये दोनों क्षमताएं एक साथ आती हैं, तो एक ऐसा आर्थिक मॉडल उभरता है, जो उत्पादन और नवाचार दोनों में संतुलन स्थापित कर सकता है। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में यह सहयोग बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर चिप्स की मांग लगातार बढ़ रही है और आपूर्ति को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं।
भारत सरकार की प्रमुख पहलें—मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया—इस साझेदारी को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकती हैं। ताइवान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की नीतिगत पहलें मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ा सकती हैं, जो फिलहाल वैश्विक स्तर पर सीमित मानी जाती है। यह न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है।
भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार भी इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 1.4 अरब से अधिक आबादी वाला यह बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और स्मार्ट डिवाइस जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती मांग का प्रतिनिधित्व करता है। ताइवान के लिए यह एक बड़ा अवसर है, जहां वह अपने उत्पादों और तकनीक के लिए एक स्थायी और विस्तारित बाजार पा सकता है। साथ ही, मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों में चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत भी ताइवान भारत के साथ सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है।
इस साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण आयाम कृषि क्षेत्र में सहयोग है। ताइवान की स्मार्ट फार्मिंग तकनीक, उन्नत बीज विकास और आधुनिक फूड प्रोसेसिंग प्रणाली भारत के कृषि क्षेत्र को नई दिशा दे सकती है। भारत, जहां कृषि अब भी बड़ी आबादी के जीवनयापन का आधार है, वहां इस तरह की तकनीकी सहायता से उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही, बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग तकनीकों के जरिए कृषि निर्यात को भी नई गति मिल सकती है।
पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय तेजी देखी गई है। व्यापार और निवेश प्रवाह में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि औद्योगिक सहयोग के नए-नए क्षेत्र सामने आ रहे हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल की ताइपे यात्रा के दौरान ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट मोबिलिटी सेक्टर में सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस दौरान संयुक्त विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए दीर्घकालिक लाभ का आधार बन सकता है।

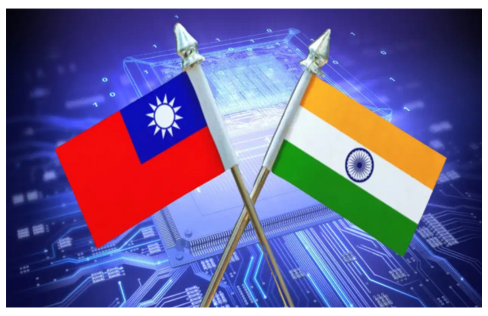

2024 में ऑर्गेनिक उत्पादों पर हुए पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA) ने कृषि और खाद्य व्यापार को नई गति दी है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के उत्पादों को एक-दूसरे के बाजार में अधिक आसानी से प्रवेश मिल सकता है, जिससे व्यापारिक बाधाएं कम होंगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, ताइवान की प्रमुख व्यापारिक संस्थाएं—ताइवान बाह्य व्यापार विकास परिषद और ताइपे कंप्यूटर एसोसिएशन—ने भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, जिससे व्यापारिक संपर्क और नेटवर्क मजबूत हुए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-ताइवान साझेदारी केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह सहयोग एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है और दोनों देशों को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावशाली बना सकता है। साथ ही, यह साझेदारी उन देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं।
कुल मिलाकर, भारत और ताइवान के बीच बढ़ती निकटता एक ऐसे समय में हो रही है, जब दुनिया नई आर्थिक संरचनाओं की तलाश में है। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए विकास के नए द्वार खोल सकती है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी एक स्थिर और संतुलित दिशा प्रदान कर सकती है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सहयोग किस तरह आकार लेता है और क्या यह वास्तव में एशिया के आर्थिक नक्शे को बदलने में सफल हो पाता है।

आरबीआई कार्रवाई के बीच Paytm ने दी राहत, सेवाएं सामान्य और कारोबार मजबूत होने का दावा

नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी One97 Communications ने हालिया घटनाक्रम के बीच उपभोक्ताओं और व्यापारियों की चिंताओं को दूर करते हुए साफ किया है कि उसकी सेवाएं पहले की तरह सुचारु रूप से जारी रहेंगी। कंपनी ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में दिया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद बाजार और उपभोक्ताओं के बीच यह सवाल उठने लगे थे कि क्या इसका असर सीधे तौर पर Paytm के मुख्य कारोबार पर पड़ेगा।
कंपनी ने अपनी नियामकीय फाइलिंग में स्पष्ट किया कि Paytm Payments Bank Limited एक अलग और स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है। इसका मतलब यह है कि One97 Communications के मुख्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं के कारोबार पर इस कार्रवाई का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी ने यह भी बताया कि उसका पीपीबीएल के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौता या वित्तीय जोखिम नहीं है, जिससे उसके संचालन पर असर पड़ सके।
कंपनी के अनुसार, उसने पहले ही 31 मार्च 2024 तक पीपीबीएल में अपने निवेश का पूरा मूल्यह्रास (write-off) कर दिया था। इसका सीधा अर्थ यह है कि मौजूदा नियामकीय कार्रवाई का कंपनी की बैलेंस शीट या वित्तीय स्थिति पर कोई नया नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कदम को कंपनी की दूरदर्शिता के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसने संभावित जोखिमों को पहले ही सीमित कर दिया।
Paytm ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उसकी सभी प्रमुख सेवाएं—जैसे यूपीआई, पेमेंट गेटवे, क्यूआर कोड आधारित भुगतान, साउंडबॉक्स और डिजिटल वेल्थ प्लेटफॉर्म—पूरी तरह से सक्रिय हैं और इनमें पीपीबीएल की कोई भूमिका नहीं है। यानी उपभोक्ता पहले की तरह मोबाइल ऐप के जरिए भुगतान, पैसे भेजना-लेना, बिल भुगतान और अन्य डिजिटल सेवाओं का उपयोग बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं।
आरबीआई ने अपने आदेश में कहा था कि Paytm Payments Bank का संचालन जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल पाया गया, जिसके चलते यह कड़ा कदम उठाया गया। हालांकि Paytm ने इस कार्रवाई को केवल पीपीबीएल तक सीमित बताते हुए कहा कि इसका उसके व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम पर कोई असर नहीं है। कंपनी ने अपने उपयोगकर्ताओं और व्यापारिक साझेदारों को भरोसा दिलाया कि उनके लेनदेन पूरी तरह सुरक्षित हैं और सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
वित्तीय प्रदर्शन के मोर्चे पर भी कंपनी ने मजबूत स्थिति का संकेत दिया है। वित्त वर्ष 2026 में लगातार तीन तिमाहियों तक लाभ दर्ज करना कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा 559 करोड़ रुपये रहा, जबकि एकमुश्त मदों को हटाने के बाद यह 369 करोड़ रुपये रहा। दिसंबर तिमाही में कर पश्चात लाभ 225 करोड़ रुपये और EBITDA 156 करोड़ रुपये (लगभग 7 प्रतिशत मार्जिन) दर्ज किया गया, जो कंपनी की परिचालन दक्षता को दर्शाता है।
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में Paytm की पकड़ भी लगातार मजबूत हो रही है। कंपनी का यूपीआई सकल व्यापार मूल्य (GMV) पिछले नौ महीनों में 35 प्रतिशत बढ़ा है, जो उद्योग की औसत वृद्धि दर 16 प्रतिशत से काफी अधिक है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि कंपनी का प्लेटफॉर्म तेजी से विस्तार कर रहा है और उपयोगकर्ताओं के बीच उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है।
विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत मार्जिन, बढ़ते लेनदेन और व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम के चलते Paytm की दीर्घकालिक संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। हालांकि, नियामकीय चुनौतियां किसी भी वित्तीय संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होती हैं, लेकिन Paytm ने जिस तरह से अपने मुख्य कारोबार को पीपीबीएल से अलग रखा है, वह उसे इस तरह के झटकों से बचाने में मदद करता है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखाया है कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन कितने महत्वपूर्ण हैं। जहां एक ओर आरबीआई का कदम सख्त निगरानी और उपभोक्ता संरक्षण का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर Paytm का स्पष्टीकरण यह भरोसा दिलाता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।
कुल मिलाकर, मौजूदा स्थिति में उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। Paytm का दावा है कि उसका मुख्य कारोबार मजबूत है, सेवाएं निर्बाध हैं और कंपनी भविष्य में भी डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी नियामकीय चुनौतियों से कैसे निपटती है और अपने विकास की रफ्तार को किस तरह बनाए रखती है।

हिमाचल के उद्योगपति और दानवीर डॉक्टर महिंद्र शर्मा ने पावन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लिए एक करोड़ एक लाख रूपये दान दिए

हिमाचल के उद्योगपति और दानवीर डॉक्टर महिंद्र शर्मा ने हिन्दुओं के आराध्य स्थल पावन पावन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में देश विदेशों से आने बाले श्रद्धालुओं को अधिकतम सुविधाएँ प्रदान करने ले लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति को एक करोड़ एक लाख रुपए दान किए । उन्होंने इस राशि का चेक विधिवत रूप से केदार नाथ मन्दिर परिसर में बद्री नाथ केदार नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी को प्रदान किया

उन्होंने यह धनराशि पावन बद्रीनाथ और केदार नाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं को अति आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए दान दी ताकि सीमित सीजन में पूरे भारत वर्ष और विदेशों से आने वाले करोड़ों हिन्दुओं को ढ़हरने,भोजन और यात्रा के दौरान हर सम्भव सुविधाएं प्रदान की जा सकें और बर्तमान सुविधाओं का विस्तार किया जा सके ताकि अधिकतम लोग सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर सकें और उनकी निजी संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही महंगी सुविधाओं पर निर्भरता को कम किया जा सके /

डॉक्टर महिंद्र शर्मा जो की बद्री नाथ केदार नाथ मंदिर समिति के सदस्य भी हैं ने इससे पहले वर्ष 2018 में लगभग तीन करोड़ रुपए की लागत से केदार नाथ मन्दिर के गर्भ गृह में चांदी का आवरण लगा कर पूरे परिसर को सुसज्जित कर चुके हैं/

केदार नाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती में पारदर्शिता लाने के हिमाचल के प्रसिद्ध उद्योगपति दानबीर महिन्दर शर्मा द्वारा वर्ष 2023 में एक ग्लास हाउस दान किया गया है जोकि मन्दिर परिसर में स्थापित कर दिया गया है/

इस ग्लास हाउस के निर्माण में उच्च गुणबत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है ताकि यह केदारनाथ धाम में सर्दियों में शून्य से पचास डिग्री नीचे तक के तापमान पर भी क्रैक न हो और सर्दियों और गर्मियों में तापमान में भिन्नता को आसानी से सहन कर सके

दानवीर महिंद्र शर्मा पावन वैष्णो देवी मंदिर में बर्ष जुलाई 2024 से वर्ष अक्तूबर 2030 तक हर बीरबर को तारकोट में पूरा दिन अटूट लंगर चलाते हैं जिसके लिए उन्होंने एक करोड़ रुपए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को दान दिए हैं/ बह तारकोट में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तत्वाधान में इस छह वर्ष की अवधि में कुल 325 लंगर आयोजित करेंगे /

उन्होंने वर्ष 2020 में माता वैष्णो देवी में दरबार में भव्य दुर्गा भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रूपये दान किया हैं ताकि श्रद्धालुओं को अति आधुनिक सुविधाएँ मिल सकें

उन्होंने अपने पैतृक जिला ऊना में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के मंदिर के गर्भ गृह को चांदी के आवरण से सुसज्जित करने के लिए लगभग तीन करोड़ रुपए दान दिए।

बद्री नाथ केदार नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी ने भारी धनराशि दान देने के लिए श्री महिंद्र शर्मा का समिति और श्रद्धालुओं की ओर से आभार जताया और धन्यवाद दिया और कहा की यह बाकि उद्योगपतियों को दान और धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करेगा /

उन्होंने कहा कि मंदिर समिति दान राशि का श्रद्धालुओं की सुविधाएं विकसित करने के लिए उपयोग करेगी।

डॉक्टर महिन्द्र शर्मा ए एन एस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक हैं / उनकी कम्पनी रियल एस्टेट , इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी में अग्रणी मानी जाती है / उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कार्यन्वित किया है /

61 वर्षीय डॉ. महिंद्र शर्मा ऊना जिले के बढेड़ा राजपूतां से संबंध रखते हैं। विज्ञान में स्नातक, एमबीए और डाक्टरेट की डिग्री ग्रहण कर चुके समाजसेवी डॉ. महिन्द्र शर्मा को जनसेवा विरासत में मिली है।

पश्चिम रेलवे द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच वृद्धि को स्थायी किया गया तथा कर्णावती एक्सप्रेस के अस्थायी टर्मिनल परिवर्तन की अवधि में वृद्धि

पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 12933/12934 वटवा/अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस में परिचालन संबंधी परिवर्तनों को जारी रखने की सूचना दी गई है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 22961/22962 वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच से 20 कोच तक की अस्थायी वृद्धि, जो पहले 27 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने तक अधिसूचित की गई थी, अब 28 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने से स्थायी कर दी जाएगी। बढ़ाए गए चार कोचों में तीन चेयर कार कोच और एक एक्जीक्यूटिव क्लास कोच शामिल हैं।
श्री विनीत ने आगे बताया कि ट्रेन संख्या 12933/12934 कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल को मुंबई सेंट्रल से बांद्रा टर्मिनस में अस्थायी रूप से परिवर्तित करने की व्यवस्था, जो पहले 27 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने तक अधिसूचित की गई थी, अब 31 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने तक जारी रहेगी। तदनुसार, इस अवधि के दौरान यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस से प्रारंभ/समाप्त होती रहेगी। ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस–वटवा कर्णावती एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से 13:55 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस पर 12:30 बजे पहुंचेगी। मार्ग के स्टेशनों के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, कर्णावती एक्सप्रेस में इस अवधि के दौरान एक एसी चेयर कार कोच की अस्थायी वृद्धि भी की जाएगी और यह ट्रेन मौजूदा 21 एलएचबी कोचों के स्थान पर 22 एलएचबी कोचों के साथ चलेगी।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें और अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं। ट्रेनों के समय, ठहराव और कोच संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्या: M247GTWPOH262706, दिनांक: 22.04.2026. कार्य का नाम: 8 व्हीलर DETC के उपकरणो एवं सब - असेंबली की आवधिक ओवरहालिंग। मु. का. प्र. / दाहोद पश्चिम रेलवे कार्यालय। **कार्य की अनुमानित लागत**: रु. 4,69,65,180/-. **बयाना राशि**: रु. 9,39,400/-. **ई-निविदा जमा करने तथा खुलने की दिनांक तथा समय**: ई-निविदा जमा करने की नियत दिनांक तथा समय 13.05.2026 को 14:30 बजे तक तथा ई-निविदा उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेगी। टेंडर नोटिस और डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट **www.ireps.gov.in/** E-Tenders / Works / IR Electrical पर उपलब्ध हैं। **AK/17**

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्या: M247GLRSCTFJ262703, दिनांक: 23.04.2026. कार्य का नाम: 1000 Amp क्षमता के CTF तथा REVERSOR का 1500 Amp क्षमता में अपग्रेडेशन / रिहेबिलीटेशन । मु. का. प्र. / दाहोद पश्चिम रेलवे कार्यालय। **कार्य की अनुमानित लागत**: रु. 2,41,42,708.40. **बयाना राशि**: रु. 4,82,900/-. **ई-निविदा जमा करने तथा खुलने की दिनांक तथा समय**: ई-निविदा जमा करने की नियत दिनांक तथा समय 14.05.2026 को 14:30 बजे तक तथा ई-निविदा उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेगी। टेंडर नोटिस और डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट **www.ireps.gov.in/** E-Tenders / Works / IR Electrical पर उपलब्ध हैं। **AK/18**

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

नीमराना में आग का कहर: कबाड़ गोदाम में जिंदा जले चार लोग, सुरक्षा इंतजामों पर उठे बड़े सवाल

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र नीमराना में शुक्रवार शाम एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के इस क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में दो नाबालिग युवतियां भी शामिल हैं, जो आग की चपेट में आकर जिंदा जल गईं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गोदाम में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों के कारण लपटें कुछ ही मिनटों में आसमान छूने लगीं और घना धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दमकल विभाग को इसे काबू में करने में करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई दमकल गाड़ियों को मौके पर लगाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण गोदाम में परफ्यूम की शीशियां तोड़ने के दौरान बीड़ी जलाना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां मौजूद ज्वलनशील केमिकल्स ने तुरंत आग पकड़ ली, जिससे विस्फोट जैसी स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आग के वास्तविक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसके लिए फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह हादसा लापरवाही का परिणाम था या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी जिम्मेदार है।

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके साथ उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, डीएसपी चारुल गुप्ता और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और चार लोगों की जान जा चुकी थी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनमें सात वर्षीय आरुषि, किशोरी कविता (करीब 16-18 वर्ष), पिकअप चालक जोनी और रविदत्त शामिल हैं। इन चारों की मौत ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। आरुषि के पिता संतराम ने बताया कि उनकी बेटी केवल खाना देने के लिए गोदाम गई थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह इस भयावह आग की चपेट में आ गई।

वहीं कविता के परिजनों के अनुसार, वह गोदाम में काम करती थी और रोज की तरह उस दिन भी अपने काम पर मौजूद थी।

इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

आग की इस घटना में गोदाम में रखा लाखों रुपये का कबाड़ पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसके अलावा वहां खड़ा एक पिकअप वाहन भी आग की भेंट चढ़ गया। आग की ऊंची लपटों और घने धुएं के कारण आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया, ताकि किसी और जानमाल का नुकसान न हो।

घटना के बाद पुलिस ने गोदाम मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी जांच की जा रही है कि गोदाम में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, और क्या वहां ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित तरीके से रखा गया था।

इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके के पास इस तरह के कबाड़ गोदाम चलाना बेहद खतरनाक है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे गोदामों को आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाए और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि यदि पहले ही उचित कदम उठाए गए होते, तो शायद यह हादसा टल सकता था।

यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी है। यह सवाल उठाती है कि औद्योगिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा मानकों का पालन कितना सख्ती से किया जा रहा है। क्या प्रशासन नियमित निरीक्षण करता है? क्या गोदाम मालिक नियमों का पालन करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है?

नीमराना की यह दर्दनाक घटना इन सभी सवालों को सामने लाती है और यह संकेत देती है कि अब केवल जांच और कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। जब तक सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा और लापरवाही पर कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे।

फिलहाल, प्रशासन जांच में जुटा है और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया, उनके लिए यह नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। यह हादसा एक ऐसी त्रासदी बन गया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और यह याद दिलाता है कि सुरक्षा में छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है।

झांसी में दिल दहला देने वाली घटना: पिता ने मासूम बेटे की हत्या के बाद खुदकुशी की, जांच में पारिवारिक कलह की आशंका

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और समाज को गहरे सवालों के सामने खड़ा कर दिया है। रक्सा थाना क्षेत्र के ढीमरपुरा गांव में शुक्रवार देर रात एक व्यक्ति ने अपने ही तीन वर्षीय मासूम बेटे की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना न केवल एक परिवार के टूटने की त्रासदी है, बल्कि यह उन मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक दबावों की ओर भी संकेत करती है, जो कभी-कभी बेहद खतरनाक रूप ले लेते हैं। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान प्रेम सिंह (उम्र लगभग 30-35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। घटना देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। उस समय घर के अन्य सदस्य बाहर सो रहे थे। इसी दौरान कमरे के भीतर कुछ असामान्य हलचल का आभास होने पर उसकी पत्नी ने अंदर झांककर देखा तो वह सन्न रह गई। कमरे के भीतर उसका पति फंदे से लटका हुआ था। यह दृश्य इतना भयावह था कि उसने तुरंत आसपास के लोगों को आवाज दी और पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही डायल 112 और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तो वहां का दृश्य बेहद दर्दनाक था। एक ओर प्रेम सिंह का शव फंदे से लटका हुआ था, वहीं दूसरी ओर उसका तीन वर्षीय मासूम बेटा जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा था। बच्चे के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान पाए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या की गई है।

क्षेत्राधिकारी सदर रामवीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह आशंका सामने आई है कि आरोपी पिता ने पहले अपने बेटे की हत्या की और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। हालांकि, घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सटीक कारणों की पुष्टि की जा सके।

इस घटना ने गांव और आसपास के इलाके में शोक और भय का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार, परिवार सामान्य प्रतीत होता था और इस तरह की घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि परिवार में समय-समय पर तनाव की स्थिति रहती थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वही इस घटना की वजह बनी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी था। पुलिस ने मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से रक्त के नमूने, हथियार और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि घटना किस क्रम में हुई और इसके पीछे की परिस्थितियां क्या थीं। जांच अधिकारी इस मामले को कई कोणों से देख रहे हैं। इसमें पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और व्यक्तिगत परिस्थितियों जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। पुलिस का मानना है कि इन सभी पहलुओं की गहन जांच के बाद ही इस घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं भले ही दुर्लभ हों, लेकिन वे समाज के लिए एक चेतावनी होती हैं। यह दिखाती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संवाद और सामाजिक सहयोग कितने महत्वपूर्ण हैं। जब व्यक्ति तनाव, अवसाद या दबाव में होता है और उसे सही समय पर सहायता नहीं मिलती, तो वह ऐसे चरम कदम उठा सकता है, जिसके परिणाम बेहद दुखद होते हैं।

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल, परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक त्रासदी है, जो यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को समझ पा रहे हैं। एक मासूम बच्चे की जान चली गई और एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया—यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो समाज को संवेदनशील और जागरूक बनने की आवश्यकता की याद दिलाती है। प्रशासन और पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पारिवारिक और मानसिक समस्याओं को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या इससे समाज में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं।

उत्तराखंड में अतिक्रमण पर सख्ती: रेलवे भूमि से हटाई गई अवैध मजार, 582 ढांचों पर चल चुका बुलडोजर

उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा अभियान अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर जिले में किच्छा–पंतनगर मार्ग पर स्थित रेलवे भूमि से एक अवैध मजार को तड़के ध्वस्त कर हटा दिया गया। जिला प्रशासन और रेलवे की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई ने राज्य में जारी व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई के साथ ही पूरे राज्य में अब तक कुल 582 अवैध संरचनाओं को हटाया जा चुका है, जो इस अभियान के बड़े पैमाने और सख्त रुख को दर्शाता है।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया रही है। संबंधित स्थल पर अतिक्रमण को लेकर पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इज्जतनगर रेलवे मंडल की ओर से 26 मई 2023 और 18 सितंबर 2025 को संबंधित पक्षों को भूमि स्वामित्व के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

25 अप्रैल 2026 को रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन से सुरक्षा बल की मांग की, ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान किसी प्रकार की बाधा या कानून-व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो। इसके बाद एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे के कर्मचारी शामिल थे। तड़के सुबह की गई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मजार को हटा दिया गया।

अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि ध्वस्तीकरण के दौरान पूरी सावधानी बरती गई और यह सुनिश्चित किया गया कि किसी प्रकार की धार्मिक भावना आहत न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच में उस संरचना के नीचे किसी प्रकार के ऐतिहासिक या धार्मिक अवशेष नहीं पाए गए। यह भी सामने आया कि यह अतिक्रमण रेलवे की प्रस्तावित विस्तार योजना और बरेली–नैनीताल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था, जिससे सार्वजनिक परियोजनाओं में देरी हो रही थी।

इस पूरे अभियान को राज्य सरकार की उस नीति के तहत देखा जा रहा है, जिसमें सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि परिवहन, सड़क निर्माण और रेलवे विस्तार जैसी परियोजनाएं तभी समय पर पूरी हो सकती हैं, जब उनके रास्ते में आने वाले अवैध निर्माणों को हटाया जाए। यही कारण है कि प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त न करने की नीति पर काम कर रहा है।

राज्य स्तर पर अब तक 582 अवैध संरचनाओं को चिन्हित कर हटाया जा चुका है। इनमें सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई इमारतें और अन्य अतिक्रमण शामिल हैं। प्रशासन का दावा है कि यह अभियान पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर चलाया जा रहा है और हर कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों को पर्याप्त अवसर दिया जाता है।

हालांकि, इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे विकास के लिए जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए अधिक सावधानी बरतने की बात करते हैं। लेकिन प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं हो सकता।

इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी गई थी। पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। स्थानीय प्रशासन ने पहले ही आसपास के लोगों को सूचना दे दी थी, जिससे किसी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति न बने।

अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयां और तेज हो सकती हैं।

सूरत में चुनावी तैयारियां पूरी, कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचीं EVM मशीनें

गुजरात के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने जिस स्तर की व्यापक और बहुस्तरीय तैयारियां की हैं, उसने पूरे चुनावी माहौल को व्यवस्थित और नियंत्रित बना दिया है। शनिवार को जिले के सभी रिसीविंग और डिस्पैचिंग सेंटर्स से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और अन्य आवश्यक चुनाव सामग्री का वितरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। यह प्रक्रिया केवल एक औपचारिक वितरण नहीं थी, बल्कि इसमें सूक्ष्म योजना, सख्त निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय देखने को मिला, जो इस बात का संकेत है कि प्रशासन चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जिला चुनाव अधिकारी और कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी के नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। सुबह से ही सभी डिस्पैचिंग सेंटर्स पर हलचल शुरू हो गई थी, जहां पोलिंग स्टाफ अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार निर्धारित समय पर पहुंचने लगा। प्रत्येक पोलिंग टीम को उनके निर्धारित मतदान केंद्र के अनुसार EVM मशीनें, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट (जहां लागू हो), मतदाता सूची, स्याही, आवश्यक फॉर्म, सीलिंग सामग्री और अन्य जरूरी उपकरण सौंपे गए। इस दौरान हर एक सामग्री की कई स्तरों पर जांच की गई, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष रणनीति अपनाई। प्रत्येक सेंटर पर

वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई, जो वितरण प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। EVM मशीनों की सीलिंग, उनकी यूनिक आईडी का मिलान, पोलिंग स्टेशन के अनुसार टैगिंग और सुरक्षित पैकिंग जैसे हर चरण को रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी की गई, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को खत्म किया जा सके।

सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार विशेष सतर्कता बरती गई। EVM मशीनों और अन्य संवेदनशील सामग्री के परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार वाहनों का उपयोग किया गया, जिनके साथ सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहा। हर वाहन को निर्धारित रूट के अनुसार ही भेजा गया और उसकी मूवमेंट पर लगातार नजर रखी गई। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। डिस्पैचिंग सेंटर्स के बाहर और अंदर सख्त चेकिंग व्यवस्था लागू की गई थी, जहां बिना अनुमति किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था।

पोलिंग अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों को इस दौरान अंतिम दिशा-निर्देश भी दिए गए। उन्हें विस्तार से बताया गया कि मतदान के दिन किस प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करना है, EVM मशीनों को किस तरह से संचालित करना है और यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे करना है। इसके साथ ही, उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद की स्थिति में तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करें और नियमों के अनुसार कार्रवाई करें।

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा गया। सभी पोलिंग टीमों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सामग्री सौंप दी गई और वे समय पर अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। अधिकांश टीमों ने शाम तक अपने केंद्रों पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मतदान के दिन कोई असुविधा न हो।

जिला चुनाव प्रशासन ने मतदाताओं के लिए भी विशेष अपील जारी की है। अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रशासन का मानना है कि जितनी अधिक मतदान प्रतिशत होगा, उतनी ही मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था बनेगी। इस बार के चुनाव में तकनीकी और प्रबंधन के स्तर पर कई नए प्रयोग भी देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, रियल-टाइम रिपोर्टिंग और त्वरित संचार व्यवस्था के जरिए चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसी भी समस्या का त्वरित समाधान भी संभव हो सकेगा।

कुल मिलाकर, सूरत में चुनाव को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, वे यह दर्शाती हैं कि प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही के मूड में नहीं है। सुरक्षा, पारदर्शिता और व्यवस्थापन के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब सभी की नजर मतदान दिवस पर टिकी है, जहां यह पूरी चुनावी मशीनरी अपनी असली परीक्षा देगी।

यदि यह प्रक्रिया इसी तरह सुचारु रूप से आगे बढ़ती है, तो सूरत का यह चुनाव एक आदर्श मॉडल के रूप में सामने आ सकता है, जहां प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी उपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों का संतुलित समन्वय देखने को मिलेगा। यह न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है कि किस तरह व्यापक योजना और कड़े अमल के जरिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं।

अलथान में छेड़छाड़ के बाद भड़का जनाक्रोश, सूरत में देर रात तक तनाव, आरोपी पुलिस हिरासत में

गुजरात के व्यस्त और तेजी से विकसित हो रहे शहर सूरत के अलथान इलाके में शुक्रवार रात घटी एक घटना ने पूरे क्षेत्र का माहौल अचानक तनावपूर्ण बना दिया। एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों तक पहुंची, गुस्से और आक्रोश का माहौल बन गया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और आरोपी को पकड़कर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को अपने कब्जे में लिया, लेकिन तब तक हालात काफी बिगड़ चुके थे।

पुलिस के अनुसार, यह घटना रात करीब 8 बजे की है, जब एक नाबालिग छात्रा ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसके साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों का ध्यान गया और उन्होंने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसे पुलिस के हवाले करने से पहले ही पीटना शुरू कर दिया। आरोपी की पहचान शेख मोहम्मद अजीज इम्तियाज के रूप में हुई है, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा।

घटना की खबर तेजी से फैलते ही आसपास के इलाकों—वराछा, कतारगाम, कापोद्रा और सरथाना—से बड़ी संख्या में लोग अलथान पुलिस स्टेशन की ओर पहुंचने लगे। कुछ ही समय में थाने के बाहर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जो

बाद में हजारों में बदल गई। लोगों में गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने थाने के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे।

स्थिति को नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। रातभर पुलिस बल को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। हालांकि मामला यहीं शांत नहीं हुआ। शनिवार दोपहर जब पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर पूछताछ के लिए लेकर पहुंची, तो माहौल एक बार फिर गरमा गया। जैसे ही लोगों को आरोपी के वहां होने की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग फिर से जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

इस दौरान महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने आरोपी के खिलाफ नारे लगाए और सख्त सजा की मांग की। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब कुछ लोगों ने पुलिस पर चप्पलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। स्थिति अचानक नियंत्रण से बाहर होने लगी और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कुछ पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई, जिसमें एक पुलिस वैन को लात मारने की घटना भी सामने आई। पुलिस ने तुरंत सुरक्षा घेरा बनाकर आरोपी को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और उसे थाने ले जाया गया। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल अलथान और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी काफी बढ़ा दी गई है, जिससे इलाके में पुलिस छावनी जैसा माहौल बन गया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यह भी कहा गया है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर समाज में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर लोगों का आक्रोश यह दर्शाता है कि वे ऐसी घटनाओं को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, वहीं दूसरी ओर भीड़ द्वारा हिंसा और कानून को अपने हाथ में लेना एक अलग चिंता का विषय बन गया है।

प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती है—एक ओर पीड़िता को न्याय दिलाना और दूसरी ओर कानून-व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।

कुल मिलाकर, सूरत के अलथान में हुई यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिक्रिया और प्रशासनिक चुनौती का भी उदाहरण बन गई है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं।